अब सौ से अधिक आबादी वाले मजरे, टोले सड़क से जुड़ेंगे

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 11 मार्च, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने नई पहल शुरू की है.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सुगम संपर्कता परियोजना की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से गांव, ग्राम पंचायत और 100 से अधिक आबादी वाले मजरा-टोला तथा मुख्यमंत्री मजरा-टोला योजना के तहत चिन्हित बस्तियों को भी सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा. परियोजना अंतर्गत सड़कों का निर्माण मनरेगा यानी बीवी-जीरामजी योजना के माध्यम से कराया जाएगा. इसके लिए प्रदेश की प्रत्येक जनपद पंचायत को रुपए 3 करोड़ तक की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार दिया गया है. मप्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा सभी जनपद पंचायतों को राशि भी आवंटित कर दी गई है. परियोजना के तहत मजरे-टोले और सांदीपनि विद्यालयों तक बनने वाली सड़कों के लिए स्थान का चयन सिपरी सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा. साथ ही सड़कों की डीपीआर तैयार करने के लिए सिपरी सॉफ्टवेयर और आरआईएमएस का उपयोग किया जाएगा.

ड्रोन से होगी निगरानी

परियोजना के तहत बनने वाली सड़कों की निगरानी ड्रोन तकनीक से की जाएगी. निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा.

28 तक डीपीआर तैयार करने के निर्देश

आयुक्त मप्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद अवि प्रसाद ने बताया कि परियोजना के तहत 28 मार्च तक डीपीआर तैयार कर उसकी तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के निर्देश दिए.

सागर में ज्ञानवीर विश्वविद्यालय का शुभारंभ

भोपाल/सागर. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बुंदेलखंड में शिक्षा का नया अध्याय लिखा जा रहा है और ज्ञानवीर विश्वविद्यालय युवाओं के सपनों को नई ऊंचाई देने का माध्यम बनेगा. उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति ज्ञान और मूल्यों पर आधारित रही है और तक्षशिला तथा नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों ने विश्व में भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रसार किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और विश्व में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है. उन्होंने महान शिक्षाविद् डॉ. हरि सिंह गौर के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से सागर में शिक्षा का नया सूर्योदय हुआ और यहां से पढ़े विद्यार्थी देश-विदेश में अपनी पहचान बना रहे हैं. सागर में ज्ञानवीर विश्वविद्यालय के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने राहतगढ़ और जेसीनगर में श्रमिकों के बच्चों के लिए आधुनिक लाइब्रेरी बनाने की घोषणा भी की. उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय बुंदेलखंड के युवाओं के सामर्थ्य और संकल्पों को नई दिशा देगा. मुख्यमंत्री ने इस पहल के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत की सराहना करते हुए कहा कि ज्ञानवीर विश्वविद्यालय अपने माता-पिता के प्रति उनकी श्रद्धा का प्रतीक है.

अंजना हत्याकांड में अब सीबीआई करेगी जांच

नई दिल्ली/सागर. सागर जिले के बरोदिया नौनागिर के के बहुचर्चित अंजना हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ऐतिहासिक और कड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने मध्य प्रदेश पुलिस की जांच थ्योरी को नकारते हुए इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है. जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एनके सिंह की बेंच ने यह आदेश जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पूर्व मंत्री की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. सबसे बड़ी लापरवाही तब सामने आई जब मुख्य गवाह अंजना की मौत हुई. चाचा राजेंद्र का शव एम्बुलेंस से लाते समय उसकी मौत हो गई थी. पुलिस ने इसे गाड़ी से गिरना बताकर केस रफा-दफा करने की कोशिश की.

सिलेंडर की जमाखोरी पर होगी सख्त कार्रवाई

मंत्री गोविन्द सिंह ने सभी कलेक्टर्स को दिए निर्देश

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 11 मार्च, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि प्रदेश में एलपीजी उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नही हो, इस हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे हैं.

उन्होंने कहा है कि सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है कि किसी भी स्थिति में वितरक स्तर पर एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी की स्थिति निर्मित नहीं हो. राजपूत ने कहा है कि वर्तमान में प्रदेश में पेट्रोल, डीजल एवं घरेलू गैस सिलेण्डर का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है एवं आपूर्ति बनी हुई है.

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य के कारण आयात में हुई रुकावट को देखते हुए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सभी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं कि एलपीजी की आपूर्ति एवं विपणन केवल घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को किया जाये. ऑयल कम्पनियों द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को नियमित रूप से गैस की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये वितरण प्रणाली में कुछ उपाय शुरू किये गये हैं. अब पिछली डिलीवरी के 25 दिन बाद ही रिफिल बुकिंग स्वीकार की जा रही है. इसका उद्देश्य कालाबाजारी और अफरा-तफरी को रोकना तथा उपभोक्ताओं को नियमित रूप से समान वितरण सुनिश्चित करना है. इन परिस्थितियों में ऑयल कम्पनियों द्वारा तय किया गया है कि वर्तमान में चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थाओं के अलावा किसी और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं (होटल, मॉल, वल्क एलपीजी का उपयोग करने वाले औद्योगिक क्षेत्र, फैक्ट्री आदि) को कॉमर्शियल एलपीजी की सप्लाई नहीं की जायेगी.

> सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया कि जिला स्तर पर खाद्य विभाग तथा ऑयल कम्पनी के अधिकारी और एलपीजी वितरकों के साथ नियमित रूप से बैठक कर वाणिज्यिक और घरेलू सिलेण्डर की उपलब्धता की समीक्षा करें. जिले के बड़े वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की भी बैठक कर उनके पास उपलब्ध स्टॉक का विवेकपूर्ण उपयोग करने एवं उनकी ईंधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वैकल्पिक ईंधन आपूर्ति/स्रोतों का उपयोग करने की सलाह दी जाये.

एसीएस स्वास्थ्य की अध्यक्षता में समिति गठित

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल,11 मार्च. राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के लिए प्रस्तावित समग्र स्वास्थ्य योजना के अंतिम प्रारूप, नीति निर्धारण के साथ ही कर्मचारी और पेंशनर्स संगठनों से परामर्श कर योजना को मंत्रि-परिषद के समक्ष अनुमोदन के लिए अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है.

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार समिति में अपर मुख्य सचिव वित्त, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग सदस्य जबकि आयुक्त

लोक स्वास्थ्य सदस्य-सचिव होंगे. समिति प्रस्तावित योजना के सभी आवश्यक तत्वों जैसे पात्रता, कवरेज, वित्तीय माडल, क्रियान्वयन संरचना तथा हितधारकों के परामर्श को समाहित कर विस्तृत योजना दस्तावेज तैयार करेगी, जिसे मंत्रि-परिषद के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा.

परियोजनाएं समय में गुणवत्ता के साथ पूरी हों

भोपाल, 11 मार्च. तुलसीराम सिलावट ने जल संसाधन विभाग के अंतर्गत निर्माणाधीन कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में और पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं.

उन्होंने कहा कि समय पर परियोजनाएं पूरी होने से जनता को उनका लाभ मिल सकेगा. साथ ही अधिकारियों को नियमित निरीक्षण कर प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, ताकि कार्यों में किसी प्रकार की ढिलाई न हो. मंत्री सिलावट ने मंत्रालय में विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक ली. बैठक में अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा, प्रमुख अभियंता विनोद कुमार देवड़ा सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी

और निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे. बैठक में नर्मदा-तापी कछार इंदौर, जल संसाधन विभाग उज्जैन और नमामि क्षिप्रा परियोजना इकाई उज्जैन के अंतर्गत निर्माणाधीन वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं की समीक्षा की गई.

मंत्री ने आगामी सिंहस्थ-2028 से जुड़े कार्यों—कान्ह डायवर्सन क्लोज डक्ट परियोजना, सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजना और क्षिप्रा नदी के दोनों तटों पर घाट निर्माण—की प्रगति की जानकारी लेकर इन्हें समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए.

परियोजनाओं के पूर्ण होने पर उज्जैन, देवास, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, झाबुआ, बुरहानपुर और धार जिलों में लगभग 5.44 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी. मंत्री ने अधिकारियों को इन परियोजनाओं की 15-15 दिन में समीक्षा कर तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए.

तीन बच्चों को कुएं में फेंकने के आरोप में मां गिरफ्तार

खरगोन, 11 मार्च. मध्यप्रदेश में खरगोन जिले के सनावद थाना क्षेत्र में अपने तीन मासूम बच्चों को कुएं में फेंकने के आरोप में एक महिला को पुलिस ने बुधवार रात गिरफ्तार कर लिया. इस घटना में तीनों बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई थी.

पुलिस अधीक्षक रवींद्र वर्मा ने बताया कि सनावद थाना क्षेत्र के ग्राम मलगांव और भोमवाड़ा के बीच स्थित एक खेत में यह घटना हुई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार नानी बाई ने अपने दो वर्षीय पुत्र अर्जुन और चार वर्षीय पुत्र करण को खेत में बने कुएं में फेंक दिया. इसके बाद वह स्वयं भी अपने लगभग 15 दिन के शिशु को लेकर कुएं में कूद गई.

उन्होंने बताया कि नानी बाई तैरना जानती थी, लेकिन घबराहट के कारण वह कुएं के अंदर मौजूद रस्सी और सीढ़ी का सहारा लेकर किसी तरह बाहर निकल आई. बाहर आने के बाद उसने शोर मचाया, लेकिन तब तक ग्रामीणों द्वारा बच्चों को बाहर निकालने से पहले ही तीनों मासूमों की पानी में डूबने से मौत हो चुकी थी. घटना की सूचना मिलते ही सनावद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. घटना के समय महिला का पति कालू मजदूरी करने के लिए खेतों में गया हुआ था.

जल संसाधन के टेंडरों की हो न्यायिक जांच : जीतू

विशेष संवाददाता

भोपाल, 11 मार्च. मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बुधवार को राज्य सरकार पर तीखा हमला करते हुए जल संसाधन विभाग की टेंडर प्रक्रिया, सिंचाई परियोजनाओं और फर्जी बैंक गारंटी के इस्तेमाल में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए.

भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में पटवारी ने सरकार की वित्तीय प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार लगातार कर्ज ले रही है. हाल ही में 5,800 करोड़ रुपये का नया कर्ज लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश की कई सिंचाई परियोजनाएं ठप पड़ी हैं और किसान पानी के लिए परेशान हैं.

> उन्होंने नौशाद और अश्विन नाटू नामक व्यक्तियों की कथित भूमिका पर भी सवाल उठाए और दावा किया कि इनका कुछ ठेकेदारों के साथ व्यावसायिक संबंध बताए जा रहे हैं. कांग्रेस नेता ने सिंचाई परियोजनाओं में तकनीकी अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कहा कि कई जगह सस्ती एचडीपीई पाइप लगाकर कागजों में महंगी डीआई पाइप का भुगतान निकाला गया है. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि पूर्व के निर्देशों के बावजूद विभाग में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली लागू क्यों नहीं की गई. पटवारी ने 2023-24 में दिए गए टेंडरों की न्यायिक जांच, विभाग में जमा सभी बैंक गारंटियों की जांच और भुगतानों का स्वतंत्र ऑडिट कराने की मांग की. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस दस्तावेजों के साथ इस मामले की जांच की मांग को लेकर सीबीआई के पास जाएगी.

उन्होंने कहा कि सरकार ने इस वर्ष को 'कृषि वर्ष' घोषित किया है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि यह 'ठेकेदारी और कमीशन का वर्ष' बनता नजर आ रहा है. पटवारी ने आरोप लगाया कि बड़े टेंडरों में कुछ चुनिंदा कंपनियां बार-बार रु, रु या रु के रूप में सामने आती हैं, जिससे यह प्रतिस्पर्धा के बजाय 'रोटेशन सिस्टम' जैसा प्रतीत होता है. उन्होंने फलोदी कंस्ट्रक्शन और जगदीश गुप्ता के स्वामित्व वाली गुप्ता कंस्ट्रक्शन का नाम लेते हुए कहा कि ये कंपनियां कई बड़े टेंडरों में लगातार दिखाई देती हैं.

संघ में नई संगठनात्मक संरचना की आहट, कल से होगी बैठक

इंदौर, 11 मार्च. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हरियाणा के समालखा में 13 से 15 मार्च तक आयोजित होगी. संघ के लिए यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसमें संगठन की कार्यप्रणाली और ढांचे में संभावित बड़े बदलावों पर चर्चा की जाएगी.

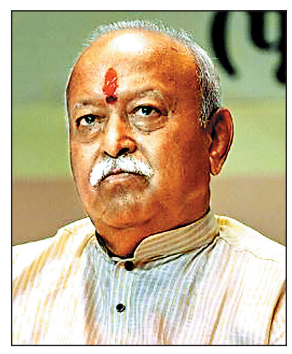

यह प्रतिनिधि सभा संघ की सर्वोच्च नीति निर्धारण संस्था मानी जाती है, जहां संगठन की भविष्य की दिशा तय होती है.

सूत्रों के अनुसार संघ अपनी पारंपरिक संगठनात्मक संरचना में बदलाव पर विचार कर रहा है. अभी तक संघ की व्यवस्था क्षेत्र, प्रांत और विभाग जैसी इकाइयों के आधार पर संचालित होती रही है. लंबे समय से यही ढांचा संघ के विस्तार और संचालन का आधार रहा है, लेकिन बदलते सामाजिक और प्रशासनिक परिवेश को देखते हुए इसे अधिक व्यावहारिक बनाने की दिशा में पहल की जा रही है.

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत संघ की संगठनात्मक संरचना को देश की प्रशासनिक प्रणाली के अनुरूप ढालने की योजना है. यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो भविष्य में संघ की इकाइयां राज्य, संभाग और जिला स्तर पर कार्य करेंगी. इसके साथ ही राज्य प्रचारक, संभाग प्रचारक और जिला प्रचारक जैसे पदों की नई संरचना विकसित होने की संभावना है. इससे संगठन की कार्यप्रणाली को अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित बनाने में मदद मिल सकती है. संघ के जानकारों का मानना है कि यह बदलाव संगठन के तेजी से बढ़ते विस्तार को ध्यान में रखकर किया जा रहा है. पिछले एक दशक में संघ की शाखाओं और उससे जुड़े विभिन्न संगठनों का देशभर में तेजी से विस्तार हुआ है. शिक्षा, सेवा और सामाजिक गतिविधियों में बढ़ती भागीदारी के कारण संगठनात्मक ढांचे को भी समय के अनुरूप ढालने की जरूरत महसूस की जा रही है.

> जानकारी के अनुसार यदि प्रतिनिधि सभा में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो नई व्यवस्था तुरंत लागू नहीं होगी. इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और वर्ष 2027 तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा गया है. समालखा में होने वाली इस बैठक में संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत सहित अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य और करीब 1450 प्रतिनिधि शामिल होंगे. बैठक में संगठनात्मक मुद्दों के साथ-साथ सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता और समकालीन चुनौतियों पर भी विचार-विमर्श होने की संभावना है.

प्रदेश के कई जिलों में पारा 38 डिग्री पार

चिलचिलाती धूप से राहगीर परेशान, ग्वालियर-चंबल सबसे ज्यादा प्रभावित

भोपाल, 11 मार्च. मध्यप्रदेश में इस वर्ष मार्च की शुरुआत से ही गर्मी ने तेजी से असर दिखाना शुरू कर दिया है. प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है.

सबसे ज्यादा असर ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में देखा जा रहा है, जहां तापमान सामान्य से करीब 6 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है. भोपाल, इंदौर और उज्जैन जैसे बड़े शहरों में भी दिन का पारा लगातार बढ़ रहा है. प्रदेश भर में चिलचिलाती धूप से आम आदमी को काफी परेशानी का समना करना है.

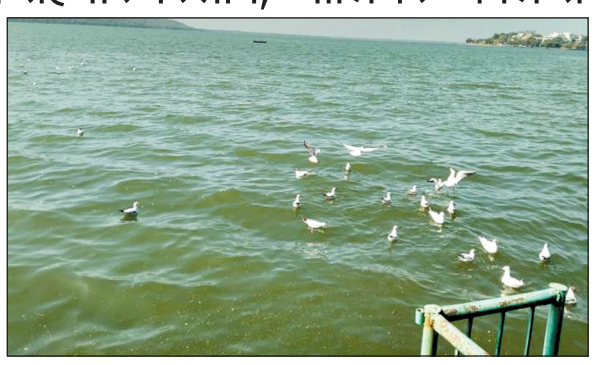

मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को प्रदेश के कई शहरों में तापमान 38 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया. धार में सबसे अधिक 39 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा सागर में 38.9 डिग्री, रतलाम और नर्मदापुरम में 38.8 डिग्री, खजुराहो में 38.3 डिग्री, गुना में 38.1 डिग्री तथा दमोह और टीकमगढ़ में 38 डिग्री तापमान दर्ज किया गया.

> पांच बड़े शहरों में ग्वालियर सबसे गर्म रहा, जहां पारा 37.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. उज्जैन में 37 डिग्री, इंदौर में 36.8 डिग्री, जबलपुर में 36.6 डिग्री और भोपाल में 36.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. प्रदेश में हवा की दिशा बदलने के कारण गर्मी में तेजी आई है. पहले हवाएं उत्तर-पूर्व दिशा से आ रही थीं, लेकिन अब पश्चिम और उत्तर-पश्चिम की ओर से चल रही हैं. इन हवाओं में नमी कम है और यह राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों से होकर मध्यप्रदेश पहुंच रही हैं, जिससे तापमान तेजी से बढ़ रहा है.

परिणय सूत्र में बंधे 176 जोड़े

झाबुआ. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत जनपद पंचायत रामा में भव्य सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

कार्यक्रम में मप्र शासन की महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुई और नवविवाहित दंपतियों को आशीर्वाद देकर उनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की.

इस अवसर पर आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में कुल 176 जोड़े विवाह बंधन में बंधे, जिनमें रामा क्षेत्र के 84 जोड़े एवं रानापुर क्षेत्र के 92 जोड़े शामिल रहे.

पूरे कार्यक्रम का आयोजन पारंपरिक रीति-रिवाजों एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ, जहां नव-दंपतियों और उनके परिजनों में विशेष उत्साह देखा गया. विवाह विधि-विधान से गायत्री परिजनों द्वारा संपन्न करवाया गया.

पेज एक का शेष

अविश्वास प्रस्ताव खारिज

मैं विपक्ष नेता से पूछना चाहता हूं कि आप तब क्यों नहीं बोले. किसने रोका था. वो तो आपका अधिकार है कि आपकी पार्टी से कौन बोलेगा.

➡क्फ संशोधन-धारा 370 जैसी चर्चाओं से राहुल गायब रहे. एसआईआर पर चर्चा थी. विपक्ष के नेता को बोला गया कि आप बोलिए. नहीं बोले. उन्होंने सदन डिस्टर्ब किया.

➡16वीं लोकसभा में राहुल गांधी ने 2014, 2015, 2017 और 2018 में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में भाग नहीं लिया. उन्होंने 16वीं लोकसभा में केंद्रीय बजट पर किसी भी चर्चा में भी हिस्सा नहीं लिया.

➡उन्होंने किसी भी सरकारी विधेयक पर चर्चा में भाग नहीं लिया. 16वें, 17वें, 19वें, 20वें और 21वें सत्रों में उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में भाग नहीं लिया. 19वें, 20वें, 22वें और 23वें सत्रों में उन्होंने केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग नहीं लिया और एक विधेयक को छोड़कर किसी अन्य विधायी चर्चा में भी भाग नहीं लिया. 18वीं लोकसभा में उन्होंने केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग नहीं लिया.

दो राज्यों को 16,450 करोड़ की सौगात

पीएम मोदी ने एलपीजी संकट की अफवाहों पर विराम लगाते हुए कहा कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं होने देंगे. भारत संकट अपने नागरिकों को अकेला नहीं छोड़ता: प्रधानमंत्री ने कहा, खाड़ी क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए आपकी चिंताएं स्वाभाविक हैं.

तैयारियां अगले सप्ताह होंगे आईएएस के थोकबंद तबादले

4 संभाग कमिश्नर, 18 जिलों में नए कलेक्टर होंगे तैनात

कन्हैया लोधी

भोपाल, 11 मार्च. प्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों के थोकबंद तबादले की तैयारियां अब अंतिम चरणों में है. सामान्य प्रशासन विभाग कार्मिक ने गुणा-भाग कर संभावित तबादले और नए अफसरों की जमावट संबंधी सूची तैयार कर ली है और इसे मुख्य सचिव कार्यालय भेज दिया गया है.

मुख्य सचिव अनुराग जैन अब इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ चर्चा कर सूची को अंतिम रूप देंगे. ऐसे में तय माना जा रहा है कि ये सूची अगले सप्ताह तक जारी हो जाएगी, नई जमावट में कम से कम चार संभागों में नए कमिश्नर तैनात किये जा सकते हैं, वहीं डेढ़ दर्जन से अधिक जिलों के कलेक्टरों को बदला जाएगा. इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष स्तर के अफसरों की भी नई जमावट हो सकती है. इस बहुप्रतीक्षित फेरबदल की चर्चा विधानसभा के मानसून सत्र से पहले ही चल रही थी, लेकिन प्रदेश में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का काम चलने के कारण मैदानी अफसरों की जमावट में कोई ज्यादा बदलाव नहीं किया जा सका था, ये इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग ने एसआईआर के काम पूरा होने तक इस कार्य में लगे अफसर और कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगा दी थी, प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया 7 फरवरी को पूरी हो चुकी है. विधानसभा का बजट सत्र भी पूर्ण हो गया है. अब होली और रंगपंचमी के बाद कभी भी आईएएस के तबादले सूची को सीएम की मंजूरी मिल सकती है.

मंत्रालय में होगी नई जमावट

संभावित फेरबदल में मंत्रालय में पदस्थ अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी भी प्रभावित हो सकते हैं. वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख सचिव अमित राठौर, सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे डीपी आहुजा को बदला जा सकता है. अपर मुख्य सचिव स्तर के अफसरों में संजय शुक्ला को दूसरी जिम्मेदारी जा सकती है.

> **भोपाल सहित एक दर्जन कलेक्टरों की हो सकती है वापसी**
>
> नई प्रशासनिक सर्जरी में कम से कम एक दर्जन कलेक्टरों की मैदानी पोस्टिंग से वापसी हो सकती है, उन्हें हटाकर नए अफसरों को भेजा जाएगा. ऐसे में वर्ष 2017 बैच के अफसरों को ज्यादा मौका मिल सकता है. इस बैच में एक दर्जन से अधिक अफसर हैं जो कि कलेक्टर बनने की प्रतीक्षा में है. वहीं कम से कम आधा दर्जन ऐसे अफसर भी होंगे.

मिले संकेतों के मुताबिक जो सूची प्रारंभिक तौर पर तैयार की गई है, उमसें भोपाल कमिश्नर संजीव सिंह, शहडोल कमिश्नर सुरभि गुप्ता, रीवा कमिश्नर बाबू सिंह जामौद और नर्मदापुरम कमिश्नर कृष्ण गोपाल तिवारी, जबलपुर कमिश्नर धनंजय सिंह भदौरिया को भी बदला जा सकता है. इसके अलावा, ग्वालियर और चंबल संभाग के कमिश्नर को बदले जाने का मामला विचाराधीन है. इंदौर में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा 3, इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स, रामगोपाल माहेश्वरी मार्ग, महाराणा प्रताप नगर, जोन-1, भोपाल से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि., इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स से मुद्रित. संपादक दिलीप झा*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-4939198, ईमेल-bhopalnav@gmail.com RNI Reg. No. 35046/56 डाक पंजीयन क्रमांक M.P/B.P.L/711/2012-14